

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 24 जनवरी, 2011

विषय- वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान संख्या-28 आयोजनागत (सामान्य) अन्तर्गत 10-दुग्धशाला का सुदृढीकरण (सामान्य) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-839/लेखा-प्रस्ताव आयो0सामान्य/2010-11, दिनांक 30-06-2010 एवं पत्रांक-2347-48/लेखा-प्रस्ताव आयो0सामान्य/2010-11, दिनांक 29-12-2010 के संदर्भ में एवं प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30-03-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में डेरी विकास विभाग को आयोजनागत पक्ष में दुग्धशाला का सुदृढीकरण हेतु रु0 50.00 लाख (रुपये पचास लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाये।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत की किया जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित निर्माण एजेन्सी द्वारा करवाया जायेगा। साथ ही राशि का तत्काल आहरण कर सम्बन्धित जनपदीय दुग्ध संघों को उपलब्ध कराया जाय।

6. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही व्यय की जाय तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है।
 7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2011 तक उपयोग कर प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
 9. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन व्यय की सूचना कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 05 तारीख तक बी0एम0-13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
 10. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-102-डेरी विकास परियोजनायें-00-आयोजनागत-10-दुग्धशाला का सुदृढीकरण-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-371(P)वि0अनु0-4, दिनांक 19-01-2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)

सचिव।

संख्या- 32-61/XV-2/1(02)/2009तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ अफसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टाफ अफसर-अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)

अनु सचिव।